MR. CHAIRMAN: Please. This is a very serious question. A number of interventions may be required. The Minister is not well-prepared. I may suggest that we should have a Half-an-Hour Discussion, when both the Minister and the Members come well-prepared. Somebody has to give notice and we shall decide.

**Rate of Interest on the Corpus of Family Pension**

*282 SHRI CO. POULOSE:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Standing Labour Committee has recommended enhancement of rate of interest on the corpus of family pension;

(b) if so, the details of the recommendations; and

(c) the steps taken by Government on these recommendations?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The Standing Labour Committee (SLC) of the Indian labour Conference had recommended that the Pension fund and the Employees Deposited-Linked Insurance Fund deposited in the Public Account should receive interest of not less than 12.5 percent as compared to the present return of 8.5 percent. The matter has been considered in consultation with the Ministry of finance. However, it has not been found possible to accept the proposal.

SHRI CO. POULOSE: Sir, my first supplementry is this: The Employees' Pension Scheme was made effective from 1995. The amount of Family Pension Fund was credited to the Employees' Pension Fund from the same date. The Government has not allowed interest rate as recommended by the Standing Labour Committee. This amount is huge. It is more than ten thousand crores of rupees. Will the Minister please disclose the amount that the Pension Fund lost by a higher interest rate not being granted, as recommended by the Standing Labour Committee from the date of merging of this Fund with the Employees' Pension Fund?

The question was actually asked on the floor of the house by Shri CO. Poulose.

**डा0 सत्यानारायण जटिया :** माननीय सभापति जी, यह प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं किंतु पेंशन के संदर्भ में जो नीतिगत मामला हैं, उस बारे में प्रश्नकर्ता जानते-होंगे कि सन् 1971 से यह पेंशन स्कीम प्रारंभ हुई । इस पेंशन स्कीम में 1.16 परसेंट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होना था और यह कामगार, प्रबंधन और सरकार का ट्राइपाट्रडिट कंट्रीब्यूशन हुआ था । इस प्रकार इस स्कीम का प्रारंभ हुआ और उस वक्त इस पेंशन स्कीम का लाभ काम करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के उपरांत मिलता था । बाद में इस पेंशन स्कीम में संशोधन होता गया । यह भी पूछा गया कि इस पेंशन स्कीम के कारण एकुमुलेशन हो गया हैं और वह राशि बहुत बढ़ गयी हैं इसलिए इस बढ़ी हुई राशि पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे कि उसका दायरा बढ़ सके ।

सभापति जी, निश्चित रूप से प्रश्नकर्ता जानते होंगे कि यह जो स्कीम हैं, इस में सरकार को 1.16 परसेंट कंट्रीब्यूशन आता हैं । बाद के समय में इस कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी में एम्प्लायर्स का शेयर 8.5 परसेंट इस पेंशन स्कीम के कंट्रीब्यूशन में आता हैं । सभापति जी, जब यह नई पेंशन स्कीम बन रही थी तो उस पेंशन स्कीम में सभी ट्रेड यूनियस का आग्रह था कि 1.16 परसेंट जो सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन जा रहा हैं, इस पर भी रेट ऑफ इंटरेट बढ़ाया जाय और चूंकि इस पेंशन स्कीम से सन् 1971 से लागू होने के बाद 1.16 परसेंट सरकार का पैसा उस में जाता हैं और जो सरकार का कंट्रीब्यूशन हैं उसी पर क्योंकि 8.5 परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा हैं अब इस पर भी यह अपेक्षा की जा रही हैं कि 12 परसेंट से अधिक इंटरेट मिले । इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय में साथ चर्चा और विचार-विमर्श किया जा रहा हैं, कितु उन का यह कहना हैं कि अभी तक इस बारे में कोई स्वीकारोक्ति नहीं मिली हैं, इसी कारण यह नहीं हुआ हैं ।

सभापति जी, चूंकि आई0 एल0 सी0 में भी यह इस प्रकार से मंजूर हुआ था और श्रम मंत्रालय ने इसे

टेक-ओवर किया हैं, लेकिन पिछले महीने वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया हैं, इसी कारण इसे शामिल करना अभी नामुमकिन हैं।

SHRI CO. POULOSE: Sir, the Government is the custodian of the public fund. It is duty-bound to see that the corpus of the Family Pension Fund receives the maximum rate of interest. The commercial banks, both private and public, offer an interest rate above 13.5 per cent on long term deposits, not less than five years. The Financial institutions, like the IDBI also offer an interest rate above 15 per cent. The Post Office Recurring Fund, Indira Vikas Patra and Kisan Vikas Patra also offer an interest rate above 15 per cent. It is an injustice done to the working class of this country. The corpus of the Fund is totally owned by the working class of this country. So, the Government should see to it that it is given a possible higher rate. The Finance Ministry is opposing the just demand of the working class. Will the hon. Minister take appropriate steps to see that a proper scheme is implemented for giving a higher rate of interest to the Family Pension Fund which has been merged with the Employees' Pension Fund?

**डा0 सत्यानारायण जटिया :** सभापति जी, सदस्य की भावना से सहमत होते हुए इस पर ब्याज की दर को बढ़ाने का काम निरंतर किया जा रहा हैं । प्रारंभ में पुरानी स्कीम में ब्याज की दर, 5.5 परसेंट थी जिसे 1.4.81 से बढ़ाकर 7.5 परसेंट किया गया हैं और 1.4.81 वाली दर को फिर बढ़ाकर 8.5 परसेंट कर दिया गया हैं। अब जहां तक मामला नई स्कीम लागू होने का हैं, उस नई स्कीम में निश्चित रूप से, जिसमें यह राशि रुपए .5308.75 करोड़ की हैं, उस पर जो ब्याज दिया जा रहा है उसमें एम्पलायर शेयर का, जैसा मैं बत चुका हूं, ब्याज 12 परसेंट से लेकर आगे जितना भी जिस प्रकार का सरकार का मापदंड हैं उसानुसार ब्याज प्राप्त करने की कोशिश की जा रही हैं। मसला केवल यह हैं, यानि थर्स्ट इसी बात पर हैं कि 1.16 परसेंट जो सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन हैं, उस सरकार के कंट्रीब्यूश पर भी ब्याज की दर बढ़ाई जाए। चूंकि सरकार का यह मत, यह मानना हैं कि यह पैसा सरकार ने इसमें जोड़े लगाया हुआ हैं और नई स्कीम की शुरुआत करने की दृष्टि से, जब 1995 में यह योजना लागू हो रही थी तो उस समय योजना लागू होने में सरकार का जो 1.16 परसेंट है वह न मिलाया जाए इस प्रकार का मामला था, किन्तु लगातार इस बात पर जोर देने के कारण भी यह, किन्तु लगातार इस बात पर जोर देने के कारण भी यह किया जा रहा हैं। अब इस पर इंटरेस्ट मिल रहा हैं। यह कहना कि सरकार के पैसे पर भी 12 परसेंट से अधिक मिले, तो वह वित्त मंत्रालय का विषय हैं और जिससे हम निरंतर संपर्क में हैं और कोशिश यह की जा रही हैं। ... (**व्यवधान**)....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: It is with the Government and not with the Finance Ministry. *(Interruptions)*

SHRI JIBON ROY: Sir, the hon. Minister is not prepared with the answer. The thing is that the Family Pension Fund is merged with the Pension Fund. The pension scheme was introduced in 1994. Because of the smallness of the corpus the Government could not keep the commitment made before the House at the time of getting the Pension Bill passed. Two basic commitments were made. Since you were not there and for knowledge sake I would mention. It was committed that every year the Government would review the scheme. The second commitment was that the Government would take unorganised workers also under the coverage of the scheme. The Government could not implement the Commitment because of the smallness of the corpus. The Government is using Rs. 11,000 crores of Family Pension Fund as a chief source for Budgetary support but they are paging only 8.5% interest on it. There are also two recommendations in this regard. One recommendation is from the Standing Committee on Labour under ILC. The second recommendation is from the Contributory Provident Fund Trust Board. ILC wanted that the rate be raised to 12.5%. The Trust Board wanted that full power be given to it to use the corpus. What is dangerous is that very recently, the hon. Finance Minister, while making his Budget speech made a

blanket announcement in the Lok Sabha that the Provident Fund can now be used by the private sector also. They can take money. Before making that announcement he did not consult the Provident Fund Trust Board which is a compulsory thing. The second thing is that when the Trust Board demanded from the Finance Ministry an authority to use the fund as they desired, the Finance Ministry issued. *(Interruptions)*. . . I wanted an answer and he did not give an answer. You should understand. *(Interruptions)* Sir, the Trust Board is an autonomous body. The Finance Ministry can only guide, the Finance Ministry cannot impose. The Finance Ministry issued a circular very recently to the effect that only 20% of the Fund can be used by the Trust Board and the rest of the fund will be distributed according to the whims of the Finance Ministry. I want to know whether the Finance Ministry has issued the circular in consultation with the Provident Fund Trustee Board or not. If it has not issued it in consultation with the Provident Fund Trust Board, do you not feel that you have violated a norm with regard to an autonomous body? What steps are you taking to implement the decision of the Standing Committee on Labour as also the Provident Fund Trust Board to increase the rate of interest?

**डा0 सत्य नारायण जटिया :** देखिए आपका प्रश्न जिस प्रकार से हैं, माकूल रूप से उसका उत्तर देने की मेरी पूरी कोशिश होगी । आपने कहा हैं कि अधिकतम लोगों को यह लाभ मिले, तो आप जानते हैं कि पुरानी जो स्कीम थी उसका लाभ, 1,70,000 लोगों को मिल रहा था । नई स्कीम जब 1995 से लागू हुई तो उसमें और लोग जुड़ते गए और इसमें 2,53,000 लोग और जुड़ और अब कुल मिलाकर 4,23,000 लोगों को इस स्कीम से लाभ मिल रहा हैं । अब इनका यह कहना हैं कि ... (**व्यवधान**)....

**डा0 सत्य नारायण जटिया :** देखिए प्रश्न सीमित हैं, प्रश्न असीमित नहीं हैं, यह असंगठित मजदूर के दायरे में अभी नहीं जा रहा । तो जो लोग सदस्य हैं, जिनका पैसा कट रहा हैं उन्हीं सदस्यों तक यह बात सीमित हैं । इसलिए 4,23,000 लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल रहा हैं और 16.11.1995 से यह स्कीम प्रारम्भ हो गई थी, इस पेंशन योजना के पहले भी स्कीम जारी थी । प्रश्न जो हैं, प्रश्न का थ्रस्ट जो मैं समझ पा रहा हूं वह यह हैं कि "जो 1.16 परसेंट कंट्रीब्यूश हो रहा हैं तो उस 1.16 परसेंट कंट्रीब्यूशन पर जो 8.5 परसेंट ब्याज़ मिल रहा हैं, उससे अधिक ब्याज चाहिए ।" यही थ्रस्ट हैं, यदि इससे कुछ अलग बात आप चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए । मैंने उत्तर दिया हैं कि वित्त मंत्रालय से इस बारे में चर्चा की जा रही हैं और वित्त मंत्रालय के निर्णय की प्रतीक्षा हैं और क्योंकि पुरानी स्कीम में ...(**व्यवधान**)....

MR. CHAIRMAN: Let him reply.

**डा0 सत्य नारायण जटिया :** सभापति जी, मै आपका संरक्षण चाहता हूं । क्योंकि पुरानी स्कीम में भी इस 1.16 परसेंट पर भी 8.5 परसेंट ही मिल रहा था और नई स्कीम मे यह 1.16 परसेंट शामिल होने की बात, क्योंकि यह ट्रेड यूनियन की मांग थी, इसलिए हो गई । तो 8.5 परसेंट को जारी रखते हुए सरकार ने 8.5 परसेंटी तक अपने आपको सीमित रखा हैं । अब यह सबका कहना हैं कि इसमें भी बाकी की तरह जो ब्याज मिल सकता हो, उस ब्याज को प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए । इसलिए श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से पत्र-व्यवहार किया हैं और उसके उत्तर की हमें प्रतीक्षा हैं । उत्तर आने पर जो अपेक्षित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी ।

SHRI JIBON ROY: Sir, my question was very simple that the Government is not implementing the recommendations of the Standing Committee and also of the PFTB. At the same time, the Government is violating the autonomous character of the PFTB. I wanted an answer to this question.

MR. CHAIRMAN: He needs a separate notice for that. *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the hon Minister is beating about the bush, as is generally done by the Ministers. Sir, the question is that the Government is not paying the normal rate of interest on a huge corpus which

belongs to the workers. We have been raising this issue in this House on a number of occasions. Everytirne— I have sympathy for the Labour Minister—the Labour Minister would come and say that they have taken up the matter with the Ministry of Finance and the Ministry of Finance is not agreeing to it. Therefore, the most important question is whether the Government has a right to exploit the money of the workers as a chief source of the fund. Sir, the rate of interest is 8.5 per cent. The Government is utilising this Fund at a very low rate of interest. The impact of this is that the pension available to a common worker is very low. The Government is not going to index the pension. The Government is not able to expand the pension scheme. The whole working class is suffering because of the low yield of the corpus. Therefore, my specific question is whether the labour Ministry will stubbornly take up this matter with the Ministry of Finance to ensure that workers are allowed by the Government to have a better rate of interest on their own corpus.

Secondly, I would like to know whether the Ministry of Finance believes that this should be done. This is not a bipartite agreement between the two. I would also like to know whether the Ministry of Labour believes that the Ministry of Finance should agree to the recommendation made by the Standing Committee on Labour. ...*(Interruptions)*... Let him say. ...*(Interruptions)*... It is unusual for the Minister to become helpless when the workers are being exploited.

**डॉ सत्यनारायण जटिया :** माननीय सभापति जी, प्रश्न ऐसा नहीं हैं और जैसा कि कहा जा रहा हैं कि इसका लाभ नहीं मिल रहा हैं, मैंने बताया हैं कि 1,70,000 लोग ... (**व्यवधान**)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the interest rate on the corpus is low. Therefore, the yield is low. Let him admit that.

**डॉ सत्यनारायण जटिया :** मैंने आपको डीटेल्स नहीं दिए हैं, आप चाहते हैं तो मैं दे देता हूं।

**श्री गुरुदास दासगुप्त :** डीटेल्स क्या हैं ? क्या इंटरेस्ट रेट कम हैं या यील्ड कम हैं ?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The question is, they have to get interest at the rate of 12.5%. It is under consideration of the Ministry of Finance.The House would like to have an assurance from the hon. Minister that he will take it up strongly with the Ministry of Finance and the Government will come out with a statement that 12.5% would be given. That is all. Nothing else.

**डॉ सत्यनारायण जटिया :** जहां तक सदस्य की भावना का मत हैं, मैं अपनी ओर से इसके बारे में पुरज़ोर कोशिश करने का आश्वासन देता हूं।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, after an assurance from the hon. Minister, I do not think that there is anything to ask. It is more so because the coverage has been increasing and the hon. Minister has also mentioned that from time to time interest rates have also been increased in view of the changed circumstances. He has given an assurance. Therefore, I do not propose to ask any supplementary.

**दिल्ली में क्वार्टरों का बिना-बारी आवंटन**

*283. **श्री ओंकार सिंह लखावत :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 8700 क्वार्टर बिना-बारी के आधार पर आबंटित किये थे,

(ख) यदि हां, तो इन आबंटनों के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या सरकार बिना-बारी आबंटन के अधिकार को बहाल करने का विचार रखती हैं, और

(घ) दिल्ली में क्वार्टर प्राप्त करने के लिए किस-किस टाइप के आवास के लिए ऐसे कितने-कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?